वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार को अफीम उत्पादकों की ओर से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे। ये अभ्यावेदन अफीम का मूल्य बढ़ाने के संबंध में थे।

पुरानी और नई दोनों ही योजनाओं में पोस्त के काश्तकारों को देय मूल्यों के निर्धारण हेतु एक ही आधार अर्थात काश्तकारों द्वारा दी जाने वाली प्रति हेक्टयर अफीम की उपज, अपनाया गया है। इस संबंध में अपनाया गया सिद्धांत यह है "प्रति हेक्टेयर जितनी अधिक उपज होगी, मूल्य दर भी उतनी अधिक होगी।"

अफीम के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के जटिल हालत को देखते हुये, अफीम को अपेक्ष कृत अधिफ प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने की जरूरत बराबर बगो हुई है जिससे हम इसका निर्यात बढ़ा सकें। पोस्त के काश्तकारों के लिये संशोधित दरें भी लाभकर हैं। इसलिये, अफीम का मूल्य बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

(ग) सरकार अफीम से व्युत्पन्न तैयार औषध द्रव्यों का बड़ी मात्रा में निर्यात करने का प्रयास कर रही है। गैर-सरकारी क्षेत्र के औषध निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अफीम आधारित औषध निर्मितियों का निर्यात बढ़ायें। सरकार तैयार औषध द्रव्यों के निर्यातों को बढ़ाने का कार्य भारतीय रसायन तथा भेषजीय निगम को सौंपने संबंधी प्रस्ताय पर भो विचार कर रही है।

बैंक जमाराशियां

2036. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान बैंक जमाराशियों में भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) जमाराशियां बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या प्रोत्साहन उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (ख) और (ख) वर्ष के पहले भाग में धीमी बढ़ोतरी के बाद, बैंक जमाराशियों में विशेष रूप से जून 1982 के मध्य से गति आई है। 11 जून, से 10 सितम्बर, 1982 के दौरान बैंक जमा राशियों में 2231 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान इसमें 1584 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। 24 सितम्बर, 1982 तफ के चालू वित्तोय वर्ष के दौरान बैंक जमाराशियों में 3354 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जोकि पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में हुई 3597 करोड़ रुपये की वृद्धि से कुछ ही कम है। इस अवधि के दौरान, बैंकों की नकदी की स्थिति में भी सुधार हुआ।

बैंक जमाओं में वृद्धि की दर कई सम्मिलित कारकों द्वारा प्रभावित होती है और जमाराशियों की वृद्धि की दर में समय-समय पर अल्पावधि घट बढ़ हो सकती है। यह मूल्यांकन करना अभी समय से पूर्व

होगा कि क्या जमाओं की वृद्धि में पिछले कुछ महीनों से हो रही कमी बराबर रहेगी और यदि ऐसा हुआ तो उसके कारण क्या हैं ।

(ग) 1 मार्च, 1982 से, भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु और मध्यम अवधि की सावधि जमाओं पर ब्याज की दर बढ़ा दी है । बैंक जमाओं समेत विशिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों से आय की सीमा को भी सरकार ने 3000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया है । इस के अलावा एक वर्ष की परिपक्वता अवधि से अधिक वाली बैंक जमाओं से ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली 2000 रुपये तक की अतिरिक्त आय को भी आयकर से मुक्त कर दिया गया है । बचतकर्त्ताओं की विभिन्न श्रेणियों की अपेक्षाओं को पूरा करने का नयी योजनाएं तैयार करके, व्यक्तियों से और अधिक बचतें जुटाने की ओर अधिक ध्यान देने के लिये भी बैंकों से कहा गया है । इन उपायों से बैंकों को जमा राशियां जुटाने में सहायता मिलने की संम्भवना है ।

Setting up of defence projects in Arkonam Tamil Nadu

2037. SHRI ERA ANBARASU: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to set up a Defence project in Arkonam, Tamil Nadu; and

(b) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) and (b). The Government are considering a proposal to set up a Naval Air Station at Arkonam. A clear picture regarding the proposal has not yet emerged.

Study on delay in commissioning of projects

2038. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the delay in commissioning of various projects undertaken by the Central Government has cost the exchequer a huge amount of money, as a result of up-ward revision of the original cost and changes of time-frames;

(b) if so, whether any in-depth study has since been undertaken on this matter; and

(c) if so, the results of the study?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Increase in project cost estimates have been noticed in projects on account of various factors, including delay in commissioning.

(b) and (c). While no in-depth study as such has been undertaken to examine this problem in general, the reasons for the increase in cost estimates are examined closely at the time of consideration of the revised cost estimates of each project. As projects are sanctioned on a fixed cost basis, without making allowance for future price escalations, such increases in project costs become unavoidable to some extent, even where there is no delay in commissioning. Apart from cost escalations, changes in the scope of the project, delays in project implementation due to factors like problems in land acquisition, delay in receipt of equipment etc., are also seen to contribute to the increase in project costs.

Indo-UK meeting of defence ministers in Delhi

2039. SHRI K. M. MADHUKAR: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether talks took place and decisions were taken at a meeting held in Delhi between the visiting Defence Minister of U.K. and Defence Minister of India; and